www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

वर्ष-14, अंक-17 01-15 सितम्बर, 2019 (पाक्षिक) ₹20

हमारे हौसलों की उड़ान के आगे आसमां भी कुछ नहीं

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में अपने आवास परिसर में तिरंगा फहराते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में तिरंगा फहराते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर उनकी समाधि 'सदैव अटल' पर उन्हें श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर उनकी समाधि 'सदैव अटल' पर उन्हें श्रद्धांजलि देते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह व भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

हैदराबाद (तेलंगाना) में भाजपा सदस्यता अभियान में हिस्सा लेते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

पोखरण (राजस्थान) में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 हम समस्याओं को न टालते हैं, न पालते हैं : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ' (सीडीएस) का पद सृजित किए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की और साथ ही देश में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान हटाने और...

वैचारिकी

परानुकरण से राष्ट्र की सृजनात्मक शक्ति समाप्त हो रही है 19

श्रद्धांजलि

बाबूलाल गौर 23

लेख

मेरे अटल जी 21

मजबूत इच्छाशक्ति से बदलाव लाते मोदी 24

अन्य

अनेक पार्टियों के नेता हुए भाजपा में शामिल 15

जुलाई, 2019 के दौरान काफी कम हुई महंगाई 18

सरकार सस्ती दर पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध 20

भारत एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्रः राजनाथ सिंह 25

सुषमा स्वराज ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सिद्ध करके दिखायाः नरेन्द्र मोदी 26

'अटलजी ने शुचिता एवं सुशासन की राजनीति को बढ़ावा दिया' 28

भूटान के साथ 10 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर 30

ट्रिपल तलाक समाप्त करना आसान नहीं थाः अमित शाह 32

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन 33

13 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' दुश्मन के लिए वज्र के समान होगा: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने एकलव्य स्टेडियम में आयोजित आस्था रैली...

14 अनुच्छेद 370 अच्छा था तो इसे स्थायी क्यों नहीं बनाया : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का समर्थन नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने...

16 चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए चंद्रयान-2 को चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त को...

17 नयी वेतन संहिता से 50 करोड़ कामगारों को लाभ

केंद्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार के अनुसार नयी वेतन संहिता से देश में करीब 50 करोड़...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

पांच वर्ष पूर्व लोग सोचते थे– क्या यह देश बदल सकता है? आज लोग कह रहे हैं- हां, मेरा देश बदल सकता है। अब देश के वातावरण में एक ही गूंज है- हां, हम भी देश बदल सकते हैं।

@AmitShah

देश का विकास करने के लिये सिर्फ एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो गरीब है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसको ऊपर उठाया जाए। लेकिन 60 के दशक के बाद कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की और बाकी पार्टियों ने इसका अनुसरण किया, इसने देश के लोकतंत्र और समाज पर बहुत बुरा असर डाला।

@JPNadda

तेलंगाना में करीब 26 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यहां ये योजना लागू नहीं है। यहां के मुख्यमंत्री को जनता से कोई सरोकार नहीं है।

facebook

राजस्थान में फैली अराजकता को लेकर हर कोई चिंतित है तथा किसान वर्ग में काफी निराशा है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, कॉलेजों में गोलियां चल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य भी ठप्प पड़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार जवाब दें कि विधानसभा चुनावों के समय जारी उनका घोषणा पत्र, क्या वोट बटोरने का जरिया मात्र था?

— **वसुंधरा राजे**

विकसित भारत का दृढ़-संकल्प लिए राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की नीतियों एवं निर्णयों से देश में सकारात्मक परिवर्तन संभव हुए हैं। आज हमारा देश उनकी दूरदर्शिता से वैश्विक स्तर पर एक नये और सशक्त भारत के रूप में उभर रहा है।

— **डॉ. रमन सिंह**

हमारी सरकार का लक्ष्य पर्यटन की दृष्टि से देवभूमि हिमाचल का समग्र विकास करना है। हम प्रदेश में ईको, सांस्कृतिक, धार्मिक व साहसिक पर्यटन पर प्राथमिकता दे रहे हैं।

— **जयराम ठाकुर**

कमल संदेश परिवार की ओर से

सुधी पाठकों को

गणेश चतुर्थी (02 सितम्बर)

की हार्दिक शुभकामनाएं!

नए युग में भारत का प्रवेश

लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को पुनः एक बार आत्मविश्वास, गहरे दृढ़ संकल्प और ऊंचे महत्वाकांक्षाओं के साथ देश को नई ऊंचाइयां छूने का आह्वान किया है। यह निरंतर छठी बार है जब प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है तथा हर एक नागरिक में 'नए भारत' के लिए नई आशा एवं संकल्प को मजबूत किया है। हर एक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रधानमंत्री के प्रयासों का प्रतिफल तब सामने आता है जब विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए उनके अपील पर करोड़ों लोग सब्सिडी एवं अन्य सहूलियतें स्वतः त्याग देते हैं। सरकार की अनेक योजनाओं एवं प्रकल्पों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारी जनसमर्थन जुटाने में सफल रहे हैं। फलतः जनभागीदारी के कारण ये कार्यक्रम जनांदोलनों का रूप ले रहे हैं। परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में भारत को अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, जिसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। राष्ट्र के नाम इस संबोधन से 'नए भारत' की आहट अब पूरे विश्व को सुनाई पड़ रही है।

गत पांच वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। कांग्रेसनीत यूपीए के भारी भ्रष्टाचार, लूट, कुशासन और पॉलिसी पैरेलिसिस का काला अध्याय समाप्त हो चुका है और सुशासन, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का युग प्रारंभ हो चुका है। नए भारत की ऐसी कार्य–संस्कृति है जो परिणामकारक है, जो दायित्वयुक्त और पारदर्शी है। भारत के पास अब ऐसी सरकार है जो देशहित में कड़े से कड़े निर्णय लेती है और जब निर्णय लेती है तब उसका क्रियान्वयन भी होता है। सरकार गरीब से गरीब, वंचित एवं शोषित, युवा एवं महिला के कल्याण में दिन–रात समर्पित है। मोदी सरकार जिसने ग्रामीण क्षेत्र, किसानों एवं मजदूरों को अपनी प्राथमिकता में रखा है, अपने परिणामकारी एवं अभिनव योजनाओं से इन्हें भारी राहत पहुंचा कर इनसे सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह एक ऐसी सरकार है जो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से लेकर 'ईज ऑफ लिविंग' के मानदण्डों पर खरी उतर रही है और देश में सकारात्मक एवं दूरगामी परिवर्तन लाने को कृतसंकल्पित है। फलतः आज पूरा विश्व यह बात मानने लगा है कि भारत व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तथा एक महान देश के रूप में विश्व पटल पर उभर चुका है जिसे अपने दायित्वों एवं लक्ष्यों का पूर्ण रूप से भान है।

गत पांच वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। कांग्रेसनीत यूपीए के भारी भ्रष्टाचार, लूट, कुशासन और पॉलिसी पैरेलिसिस का काला अध्याय समाप्त हो चुका है और सुशासन, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का युग प्रारंभ हो चुका है।

मोदी सरकार ने चाहे आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात हो या चन्द्रमा से लेकर मंगल तक जाने की योजना, अनगिनत उपलब्धियों का अंबार लगा दिया है। इससे उपलब्धियों के व्यापक होते दायरे का आभास होता है जबकि एक सरकार राष्ट्र की गौरवमयी यात्रा में हर क्षेत्र में अपने दायित्वों के प्रति सजग है। आज जबकि गरीब से गरीब व्यक्ति को पक्का घर, मुफ्त गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन, पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और अन्यान्य आवश्यक सुविधायें प्राप्त हो रही हैं, पूरा राष्ट्र आने वाले पांच वर्षों में पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। मोदी सरकार की 'स्पीड, स्केल, स्किल' के साथ कार्य करने का परिणाम आधारभूत संरचना के लिए भारी–भरकम कार्य–योजना में देखा जा सकता है जिसके अंतर्गत आने वाले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ के निवेश का संकल्प है। हर दिन भारत नई ऊंचाइयों को छूने को तत्पर है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में नित नया इतिहास रचा जा रहा है।

एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार कैसे–कैसे परिवर्तन ला सकती है, इसका पूरा विश्व आज साक्षात्कार कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति, सरकार के हर निर्णय में स्पष्ट दिखती है। देश की जनता का भारी विश्वास अर्जित कर श्री नरेन्द्र मोदी देश को एक मजबूत सरकार दे रहे हैं जिससे हर क्षेत्र में हो रहे कायाकल्प को स्पष्ट देखा जा सकता है। पिछले चुनावों में निरंतर मिले व्यापक जन–समर्थन का परिणाम है कि आज मोदी सरकार कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर राष्ट्रीय एकता–अखंडता, विकास एवं सुशासन की नई गाथा लिख रही है। पिछली बार से भी बड़ा जनादेश प्राप्त कर सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार ने केवल 70 दिनों में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं, जिसकी पिछले 70 सालों में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कई दशकों में सर्वाधिक सफल संसदीय सत्र के साथ–साथ आतंकवाद, तीन तलाक, धारा 370 एवं 35ए की समाप्ति एवं जम्मू–कश्मीर का पुनर्गठन इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों के साथ लिखा जाएगा। आज जब श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में एक करिश्माई, दूरदर्शी एवं सक्षम नेतृत्व के प्रति पूरा देश आश्वस्त है, भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है जब संपूर्ण राष्ट्र व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से स्वयं अपनी विकास गाथा लिख रहा है और मां भारती की सेवा में समर्पित हो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्रति कृतसंकल्पित है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

हम समस्याओं को न टालते हैं, न पालते हैं: नरेन्द्र मोदी

'चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ' की घोषणा और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर जोर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ' (सीडीएस) का पद सृजित किए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की और साथ ही देश में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के सरकार के कदम की पृष्ठभूमि में श्री मोदी ने कहा "हम समस्याओं को न टालते हैं, न पालते हैं। अब समस्याओं को टालने और पालने का समय नहीं है।" उन्होंने कहा, "देशवासियों ने जो काम दिया, हम उसे पूरा कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा, ''हम समस्याओं को टालते भी नहीं और पालते भी नहीं हैं। अब न टालने का समय है और न ही पालने का समय है। सरकार बनने के 70 दिनों भीतर संसद के दोनों सदनों ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के निर्णय का अनुमोदन किया।" श्री मोदी ने कहा, ''देशवासियों ने जो काम दिया, हम उसे पूरा कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर हर सरकार ने कुछ न कुछ प्रयास किया, लेकिन इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं। श्री मोदी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सपनों को

पंख लगें, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, ''जो लोग अनुच्छेद 370 की वकालत कर रहे हैं उनसे देश पूछ रहा है कि अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण था तो इसे आप लोगों ने स्थायी क्यों नहीं किया, अस्थायी क्यों बनाए रखा?" उन्होंने कहा, ''नयी सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में सभी क्षेत्रों में हर प्रयास को बल दिया गया है, हम पूरे समर्पण के साथ सेवारत हैं।"

तीन तलाक के खिलाफ हाल ही में संसद से पारित विधेयक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन भी किया गया।

लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण में मोदी ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि सेना के तीन अंगों के प्रमुख के तौर पर 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ' (सीडीएस) का पद सृजित किया जाएगा।

श्री मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सीडीएस सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगा और उन्हें प्रभावी नेतृत्व देगा।

जो लोग अनुच्छेद 370 की वकालत कर रहे हैं उनसे देश पूछ रहा है कि अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण था तो इसे आप लोगों ने स्थायी क्यों नहीं किया, अस्थायी क्यों बनाए रखा? नयी सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में सभी क्षेत्रों में हर प्रयास को बल दिया गया है, हम पूरे समर्पण के साथ सेवारत हैं।

प्रधानमंत्री ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की जरूरत पर एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा देश को महान बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने 'एक देश, एक कर' के सपने को सच किया और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक देश, एक ग्रिड की उपलब्धि भी हासिल की है

श्री मोदी ने कहा कि अब चर्चा एक देश एक चुनाव को लेकर है, यह देश को महान बनाने के लिए अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए नयी चुनौतियां पेश करता है। श्री मोदी ने कहा कि इससे निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या चिंता का विषय है और समाज का एक छोटा वर्ग जो अपना परिवार छोटा रखता रहा है, वह सम्मान का हकदार है। जो वे कर रहे हैं वह एक प्रकार की देशभक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि अगर जनता शिक्षित और स्वस्थ है तो देश भी शिक्षित और स्वस्थ बनेगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में आबादी नियंत्रण के लिये छोटे परिवार पर जोर दिया और कहा कि आबादी समृद्ध हो, शिक्षित हो तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कालाधन समाप्त करने के लिये उठाया गया हर कदम स्वागत योग्य है क्योंकि इन समस्याओं के कारण देश को पिछले 70 साल में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा ''हम हमेशा ईमानदारी को पुरस्कृत करेंगे।"

श्री मोदी ने कहा, ''आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकता के मुताबिक, आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया गया है।"

लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण की मुख्य बातें

❖ स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं।

वर्षा और बाढ़: आज देश के अनेक भागों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ सभी संगठन, नागरिकों का कष्ट कम कैसे हो, सामान्य परिस्थिति जल्दी कैसे लौटे, उसके लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं।

अनुच्छेद 370: दस हफ्ते के भीतर-भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद, 70 दिन के भीतर-भीतर अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का काम भारत के दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। आज लाल किले से मैं जब देश को संबोधित कर रहा हूं, मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिन्दुस्तानी कह सकता है- One Nation, One Constitution.

जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद, 70 दिन के भीतर-भीतर अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का काम भारत के दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। आज लाल किले से मैं जब देश को संबोधित कर रहा हूं, मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिन्दुस्तानी कह सकता है- One Nation, One Constitution.

तीन तलाक: दस हफ्ते के भीतर-भीतर हमारे मुस्लिम माताओं और बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया। अगर इस देश में, हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल-विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन-देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं।

आतंक से जुड़े कानून: आतंक से जुड़े कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम किया गया।

किसान सम्मान निधि: हमारे किसान भाइयों-बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते में transfer करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है।

किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन: हमारे किसान भाई-बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई-बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि कभी उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है।

जल शक्ति अभियान: जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा, यह भी चर्चा होती है, उन चीजों को पहले से ही सोच करके, केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाएं इसके लिए एक अलग जल-शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है।

जल-जीवन मिशन: हम आने वाले दिनों में जल-जीवन मिशन को आगे ले करके बढ़ेंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले वर्षों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम इस मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प लिया है।

चिकित्सा कानून: हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टरों की जरूरत है, आरोग्य की सुविधाएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। Medical Education को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून हमने बनाए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

❖ बच्चों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून प्रबंधन आवश्यक था। हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है।

❖ अगर 2014 से 2019 आवश्यकताओं की पूर्ति का दौर था, तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा-आकांक्षा पूरी हो, यह हम सब का दायित्व है। वहां के मेरे दलित भाइयो-बहनो को, देश के अन्य दलितों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो उनको भी मिलने चाहिए। वहां हमारे कई ऐसे समाज और व्यवस्था के लोग चाहे वह गुर्जर हों, बकरवाल हों, गद्दी हों, सिप्पी हों, बाल्टी हों- ऐसी अनेक जनजातियां, उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। भारत विभाजन हुआ, लाखों-करोड़ों लोग विस्थापित होकर आये उनका कोई गुनाह नहीं था लेकिन जो जम्मू-कश्मीर में आकर बसे, उनको मानवीय अधिकार भी नहीं

मिले, नागरिक के अधिकार भी नहीं मिले।

जम्मू-कश्मीर के लोगों का योगदान: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सुख-समृद्धि और शांति के लिए भारत के लिए प्रेरक बन सकता है। भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अब, जम्मू-कश्मीर का सामान्य नागरिक भी दिल्ली सरकार को पूछ सकता है। उसको बीच में कोई रुकावटें नहीं आएंगी। यह सीधी-सीधी व्यवस्था आज हम कर पाए हैं।

एक राष्ट्र एक कर: GST के माध्यम से हमने One Nation, One Tax के सपने को साकार किया है। पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में One Nation, One Grid को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। One Nation, One Mobility Card- इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया है और आज चर्चा चल रही है, "एक देश, एक साथ चुनाव।" यह चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए।

GST के माध्यम से हमने One Nation, One Tax के सपने को साकार किया है। पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में One Nation, One Grid को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। One Nation, One Mobility Card- इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया है और आज चर्चा चल रही है, "एक देश, एक साथ चुनाव।" यह चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए।

जनसंख्या विस्फोट: जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है लेकिन हमारे देश में एक जागरूक वर्ग भी है, जो इस बात को भली-भांति समझता है। उनके सम्मान की आवश्यकता है। समाज के बाकी वर्गों को जोड़कर जनसंख्या विस्फोट की हमें चिंता करनी ही होगी।

भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद: भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद ने हमारे देश का कल्पना से परे नुकसान किया है और दीमक की तरह हमारे जीवन में घुस गया है। यह एक ऐसी बीमारी है, जिसको हमने निरंतर Technology का उपयोग करते हुए निरस्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

लोगों के जीवन में सरकार का दखल: आजाद भारत का मतलब मेरे लिए यह है कि धीरे-धीरे सरकारें लोगों की जिंदगी से बाहर आएं। ऐसा Eco-system हमको बनाना ही होगा। न सरकार का दबाव हो, न सरकार का अभाव हो, लेकिन हम सपनों को लेकर आगे बढ़ें। Ease of living आजाद भारत की आवश्यकता है।

Incremental progress बनाम High Jump: हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन incremental progress, उसके लिये देश अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है, हमें ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी।

आधुनिक ढांचागत विकास: हमने तय किया है कि इस कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक Infrastructure के लिए लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी नई व्यवस्था विकसित होंगी।

5 Trillion Dollar Economy: हमने 5 Trillion Dollar Economy का सपना संजोया है। आजादी के 70 साल बाद हम दो Trillion Dollar Economy पर पहुंचे थे, लेकिन पिछले पांच साल के भीतर हम लोग दो Trillion से तीन Trillion पहुंच गए। इस गति से हम आने वाले पांच साल में 5 Trillion Dollar Economy बन सकते हैं।

ग्रामीण विकास और किसानों की आय: आजादी के 75 साल में देश के किसान की आय दो गुनी होनी चाहिए, हर गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए, हर परिवार के पास बिजली होनी चाहिए, हर गांव में Optical Fiber Network और Broadband की Connectivity हो, साथ ही साथ Long Distance Education की सुविधा हो।

- हमारी समुद्री संपत्ति, Blue Economy इस क्षेत्र पर हम बल दें। हमारे किसान अन्नदाता है, ऊर्जादाता बनें। हमारे

किसान, ये भी Exporter क्यों न बनें। हमारे देश को Export बढ़ाना ही होगा। हमारा हर जिला Export Hub बनने की दिशा में क्यों न सोचें। हिन्दुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से कुछ न कुछ export न होता हो। Value addition वाली चीजें दुनिया के अनेक देशों तक export हों।

पर्यटन: हमारा देश Tourist Destination के लिए दुनिया के लिए अजूबा हो सकता है। हम सभी देशवासी तय करें कि हमें देश के tourism पर बल देना है। जब tourism बढ़ता है, कम से कम पूंजी निवेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। देश की economy को बल मिलता है। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने के पहले हम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 tourist destinations पर जाएंगे।

भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। आतंकवाद को पनाह, प्रोत्साहन और export करने वाली ताकतों को उजागर करने में दुनिया के देशों के साथ मिलकर भारत अपनी भूमिका अदा करें, हम यही चाहते हैं। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में हमारे सैनिकों, सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनको नमन करता हूं।

स्थिर सरकार– भरोसेमंद नीति: जब Government stable होती है, policy predictable होती है, व्यवस्थाएं stable होती है तो दुनिया का भी एक भरोसा बनता है। विश्व भी भारत की political stability को बड़े गर्व और आदर के साथ देख रहा है।

महंगाई और विकास में संतुलन: आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि महंगाई को control करते हुए हम विकास दर को बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण समीकरण को ले करके चले हैं।

अर्थव्यवस्था: हमारी अर्थव्यवस्था के fundamentals बहुत मजबूत हैं। जीएसटी और IBC जैसे सुधार लाना अपने आप में एक नया विश्वास पैदा करते हैं। हमारे निवेशक ज्यादा कमाएं, ज्यादा निवेश करें और ज्यादा रोजगार पैदा करें। हम wealth creator को आशंका की नजरों से न देखें। उनका गौरव बढ़ना चाहिए और wealth create नहीं होगी तो wealth distribute भी नहीं होगी। अगर wealth distribute नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भलाई नहीं होगी।

आतंकवाद: भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। आतंकवाद को पनाह, प्रोत्साहन और export करने वाली ताकतों को उजागर करने में दुनिया के देशों के साथ मिलकर भारत अपनी भूमिका अदा करें, हम यही चाहते हैं। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में हमारे सैनिकों, सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनको नमन करता हूं।

भारत के पड़ोसी देश– बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हमारा पड़ोसी और एक अच्छा मित्र अफगानिस्तान चार दिन बाद 100वीं आजादी का उत्सव मनाने जा रहा है। मैं अफगानिस्तान के मित्रों को अनेक-अनेक शुभकानाएं देता हूं।

सैन्य सुधार: हमारे देश में सैन्य व्यवस्था, सैन्य शक्ति, सैन्य संसाधन - उसके Reform पर लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। अनेक सरकारों ने इसकी चर्चा की है। अनेक commission बैठे हैं, अनेक रिपोर्ट आई हैं और सारे रिपोर्ट करीब-करीब एक ही स्वर को उजागर करते रहे हैं। हमारी पूरी सैन्यशक्ति को एकमुश्त होकर एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल, थल, नभ में तीनों सेनाएं एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़ें। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम Chief of Defense Staff- CDS की व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं को शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिन्दुस्तान की सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और reform तथा बल देने

हम भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए मिशन के रूप में काम करेंगे: प्रकाश जावडेकर

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में लोगों से भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त बनाने की अपील फिर से की है, जिसे ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस दिशा में की जा रही सभी पहलों तथा अभियानों की समीक्षा करेगा।

श्री जावड़ेकर ने ब्राजील के साओ पाउलो से 15 अगस्त को जारी अपने एक वक्तव्य में कहा, 'भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त बनाने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों की सहभागिता के साथ एक व्यापक सार्वजनिक अभियान शुरू किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, ताकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से इसे एक जन अभियान में तब्दील करने के लिए एक ठोस योजना बनाई जाएगी।'

इससे पूर्व एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत को प्लास्टिक के एकबारगी इस्तेमाल से मुक्त करने का आह्वान किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी आगे आएं।"

अपने ट्वीट संदेशों में श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास, सबका विश्वास, सुरक्षा, जनसंख्या वृद्धि और प्रत्येक परिवार के लिए शुद्ध पेयजल के प्रावधान सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

श्री जावड़ेकर ने कहा, "प्रधानमंत्री ने जोरदार संदेश दिया है- पिछले पांच वर्षों में सरकार ने लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की, किन्तु अब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी।"

श्री जावड़ेकर ने जोर देकर कहा, "प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पांच वर्ष के लिए एक रोडमैप दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सशक्त नेतृत्व में भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।"

वाला काम है।

स्वच्छता अभियान: मैंने इसी लाल किले से 2014 में स्वच्छता की बात कही थी। कुछ ही सप्ताह बाद बापू की 150वीं जयंती, 02 अक्तूबर को भारत अपने-आपको खुले में शौच मुक्त राष्ट्र घोषित कर पाएगा। राज्यों, गांवों, नगर पालिकाओं और मीडिया ने स्वच्छता अभियान को जन-आंदोलन बना दिया।

प्लास्टिक मुक्त भारत: मैं एक छोटी-सी अपेक्षा आज आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या हम इस 02 अक्तूबर को भारत को single use plastic से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके लिए हर नागरिक, नगरपालिकाएं, महानगर-पालिकाएं और ग्राम पंचायतें सब मिलकर प्रयास करें।

मेक इन इंडिया: Made in India Product, हमारी प्राथमिकता क्यों न होनी चाहिए? हमें lucky कल के लिये local product पर बल देना है। देश की Economy में भी इसके कारण हम मदद कर सकते हैं।

Digital Payment: हमारा digital platform बड़ी मजबूती के साथ उभर रहा है, लेकिन हमारे गांव में, छोटी-छोटी दुकानों में भी, हमारे शहर के छोटे-छोटे मॉल में भी हम क्यूं न Digital payment पर बल दें?

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग: हम chemical fertilizer, pesticides का उपयोग करके धरती के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। क्या हम 10 percent, 20 percent, 25 percent अपने खेत में chemical fertilizer को कम करेंगे, हो सके तो मुक्तिकर अभियान चलाएंगे। मेरे किसान मेरी इस मांग को पूरा करेंगे यह मुझे पूरा विश्वास है।

प्रगति के नए आयाम: हमारे देश के professionals की आज पूरी दुनिया में गूंज है। हमारा चंद्रयान तेजी से चांद के उस छोर की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां अब तक कोई नहीं गया है। आज दुनिया के खेल के मैदानों में मेरे देश के 18 से 22 साल के बेटे-बेटियां हिन्दुस्तान का तिरंगा झंडा फहरा रही हैं।

नए लक्ष्य: आने वाले दिनों में गांवों में डेढ़ लाख wellness center बनाने होंगे, हर तीन लोकसभा के बीच एक medical college, दो करोड़ से अधिक गरीब लोगों के लिए घर, 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाना है। सवा लाख किलोमीटर गांव की सड़के बनानी हैं और हर गांव को Broadband connectivity, optical fiber network से जोड़ना है। 50 हजार से ज्यादा नये start up का जाल बिछाना है।

समता मूलक समाज: भारत के संविधान के 70 साल हो गए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने और यह वर्ष महत्वपूर्ण है, गुरू नानक देव जी का 550वां पर्व भी है। आइये, बाबा साहेब अम्बेडकर, गुरू नानक देव जी की शिक्षा को ले करके हम आगे बढ़ें और एक उत्तम समाज का निर्माण, उत्तम देश का निर्माण, विश्व की आशाओं-अपेक्षाओं के अनुरूप भारत का निर्माण करें। ■

'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' दुश्मन के लिए वज्र के समान होगा: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने एकलव्य स्टेडियम, जींद (हरियाणा) में 16 अगस्त को आयोजित आस्था रैली में अपना भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदीजी ने देश की जनता और सरदार बल्लभ पटेल के सपने को पूरा किया है। मोदी सरकार ने देश को एक किया और जम्मू-कश्मीर से 370 हटाकर वहां विकास की राह खोली। उन्होंने 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' को देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' दुश्मन के लिए वज्र के समान होगा।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के कारण बची हुई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते और उनको बस मां भारती की परवाह है। यही कारण है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि मोदीजी ने 75 दिनों में वह कर दिखाया जो देश में 70 साल में नहीं हुआ था।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' की नियुक्ति का बड़ा कदम उठाया है। यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे देश की तीनों सेनाएं बेहतर तालमेल से काम कर सकेंगी। यह दुश्मन के लिए वज्र के समान साबित होगा। अमित शाह ने देश और हरियाणा के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्योरा भी दिया।

श्री शाह ने कहा, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकसूत्र में बंध चुका है। मोदीजी ने मां भारती का गौरव बढ़ाया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा ऊपर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए आशीर्वाद दे रही होगी।

श्री शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल की भी जमकर तारीफ की और हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जाति व वर्ग की राजनीति करने वाले नेताओं ने हरियाणा में नफरत और भेदभाव का माहौल बना रखा था। मनोहरलाल की सरकार ने इसे खत्म कर पूरे राज्य का समान विकास कराया और जनता में उम्मीद की लौ जलाई।

उन्होंने कांग्रेस और चौटाला परिवार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और चौटाला परिवार ने हरियाणा का सत्यानाश किया। मनोहरलाल की सरकार ने नौकरियों में भेदभाव और भ्रष्टाचार खत्म किया। उन्होंने राज्य में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। श्री अमित शाह ने कहा कि हम हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमें इसके अनुरूप कामयाब बनाएगी।

कांग्रेस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वह विकास के लिए खर्च पैसों का हिसाब किताब और आंकड़े लेकर जनता के बीच जाएं, हमारे मुख्यमंत्री उनसे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और चौटाला सरकारों पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा, पूर्व सरकारों में हरियाणा जमीन के व्यापार के लिए जाना जाता था। सरकारें बिल्डरों के हाथ में कठपुतलियां बनकर खेलती थी और नौकरियां व्यवसाय थीं। लेकिन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने भ्रष्टाचार को भूतकाल बना दिया है।

श्री शाह ने कहा कि हरियाणा से सभी लालों के जाने के बाद हमारा लाल (मनोहरलाल) आया है। हरियाणा में अब जातिवाद खत्म हो चुका है। तबादलों में पारदर्शिता लाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को भारी राहत दी। लिंगानुपात में सुधार हो या ऑनलाइन

तबादले या आशा वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में इजाफा, मनोहर सरकार ने शानदार काम किया है।

उन्होंने कहा कि हुड्डा की सरकार में जहां 13वें वित्त आयोग ने हरियाणा को सिर्फ 22 हजार करोड़ रुपये दिए थे वहीं मनोहर की सरकार के बेहतरीन काम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 58 हजार करोड़ रुपये 14वें वित्त आयोग से हरियाणा को दिलवाए। रैली में हरियाणा भाजपा की ओर से अमित शाह को सदस्यता अभियान की एक क्विंटल वजन के बराबर फार्म भेंट किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व रैली के आयोजक श्री बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, राज्य के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, कैबिनेट मंत्री कविता जैन, कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ और राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर भी रैली में मौजूद थे। ■

अनुच्छेद 370 अच्छा था तो इसे स्थायी क्यों नहीं बनाया: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का समर्थन नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति में शामिल रही है जबकि वह जानती थी कि यह अनुच्छेद राष्ट्र हित में नहीं है। उन्होंने कहा, ''मोदीजी ने एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान को महसूस किया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है, जबकि वह कहती है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है।''

गत 18 अगस्त को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि अगर अनुच्छेद-370 अच्छा था तो इसे स्थायी क्यों नहीं बनाया? आपके पास एक समय 400 से अधिक सांसद थे।'' भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान से हैदराबाद आए वे नेता बन गए, लेकिन जिन्होंने जम्मू-कश्मीर को अपना घर बनाया वे पार्षद भी नहीं बन सकते। अब अनुच्छेद-370 खत्म करने से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें होंगी।

उन्होंने कहा कि 'देश के लोग चाहते थे कि आर्टिकल 370 रद्द हो और इसीलिए केंद्र की भाजपा सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। आर्टिकल 370 दशकों पहले हट जाना चाहिए था।' इतना ही नहीं श्री नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए तीन तलाक पर केंद्र सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 'तीन तलाक रद्द कर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा गया है।'

श्री नड्डा ने कांग्रेस के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला और सवाल पूछा। उन्होंने केसीआर सरकार पर केंद्र सरकार की योजना को राज्य में लागू नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'तेलंगाना के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो जाएंगे, यही सोचकर केसीआर सरकार ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना शुरू नहीं की है। इससे देश भर में अब तक 55 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है।' ■

अनेक पार्टियों के नेता हुए भाजपा में शामिल

तेदेपा के 60 नेता भाजपा में शामिल

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के करीब 60 प्रमुख नेता और उनके हजारों समर्थक 18 अगस्त को भाजपा में शामिल हो गए। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली।

जून में तेदेपा छोड़कर भाजपा में आए लंका दिनकर ने कहा कि हमारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इकाई के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है। हजारों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इनमें कुछ राष्ट्रीय स्तर के बड़े नाम भी शामिल हैं। कुछ राज्य और जिलास्तर पर बड़े नेता हैं। सरकार के तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने और अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद अब भी बहुत से नेता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायक भाजपा में शामिल

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के 13 में से 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव की उपस्थिति में विधायकों ने 13 अगस्त को सदस्यता ली। अब एसडीएफ के पास पूर्व मुख्यमंत्री श्री पवन कुमार चामलिंग समेत 3 विधायक बचे हैं। राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी की सरकार है। उसके पास कुल 16 विधायक हैं। 3 सीटें खाली हैं।

श्री राम माधव ने कहा, ''एसडीएफ के 13 विधायक थे। पार्टी के विधायक दल ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। भाजपा की केंद्र में सरकार है। अब तक पूर्वोत्तर में सिक्किम को छोड़कर बाकी राज्यों में भाजपा का क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन था। अब सिक्किम में एसडीएफ के विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद वहां भी सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकेगा।'' अगर किसी पार्टी के दो तिहाई विधायक दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है।

भाजपा में शामिल हुए टीडीपी और जन सेना के नेता

आंध्र प्रदेश के टीडीपी और जन सेना पार्टी के कुछ नेता 1 अगस्त को भाजपा में शामिल हो गए।

पूर्व सांसद गंगुला प्रताप रेड्डी (नंद्याल), पसुपुलेटी सुधाकर (कावली से जन सेना टिकट पर लड़ने वाले उम्मीदवार), कंचर्ला हरि प्रसाद (सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त), डी. वेंकैया (टीडीपी, चित्तूर ओबीसी सेल सेक्रेटरी), सी. चंद्रप्पा (बीसी वेल्फेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट-श्रीकालहस्ती), शेख निजामुद्दीन, मजहर बैग भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर राव और आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया।

इस मौके पर श्री मुरलीधर राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में देश तेजी से विकसित हो रहा है और विकास में भागीदार बनने के उद्देश्य से अन्य पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ■

चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए चंद्रयान-2 को चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष एजेंसी के बेंगलुरु मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि 'लूनर ऑर्बिट इंसर्शन' (एलओआई) प्रक्रिया सुबह नौ बजकर दो मिनट पर सफलतापूर्वक पूरी हुई। प्रणोदन प्रणाली के जरिए इसे संपन्न किया गया।

इसरो ने कहा, ''यह पूरी प्रक्रिया 1,738 सेकेंड की थी और इसके साथ ही चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया।" इसरो ने कहा कि इसके बाद यान को चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्र ध्रुवों के ऊपर से गुजर रही इसकी अंतिम कक्षा में पहुंचाने के लिए चार और कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसके बाद लैंडर 'विक्रम' दो सितंबर को ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा।

इसरो ने कहा कि सात सितंबर को चंद्रमा की सतह पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' कराने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले लैंडर संबंधी दो कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। बेंगलूरु के नजदीक ब्यालालू स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क (आईडीएसएन) के एंटीना की मदद से बेंगलूरू स्थित 'इसरो, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क' (आईएसटीआरएसी) के मिशन ऑपरेशन्स कांप्लेक्स (एमओएक्स) से यान की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

देश के कम लागत वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम को पंख लगाते हुए इसरो के सबसे शक्तिशाली तीन चरण वाले रॉकेट जीएसएलवी-एमके3-एम1 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई को चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया था। प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान-2 ने गत 14 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्र पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया था।

इसरो का यह अब तक का सबसे जटिल और सबसे प्रतिष्ठित मिशन है। यदि सब कुछ सही रहता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत, चांद की सतह पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने वाला चौथा देश बन जाएगा।

'चंद्रयान-2' मिशन भारत के लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। इससे पहले गत 15 जुलाई को रॉकेट में तकनीकी खामी का पता चलने के बाद 'चंद्रयान-2' का प्रक्षेपण टाल दिया गया था। समय रहते खामी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने इसरो की सराहना की थी।

'चंद्रयान-2' चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। इससे चांद के अनसुलझे रहस्य जानने में मदद मिलेगी। यह ऐसी नयी खोज होगी जिसका भारत और पूरी मानवता को लाभ मिलेगा। पहले चंद्र मिशन की सफलता के 11 साल बाद इसरो ने भू-स्थैतिक प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-मार्क।।। के जरिए 978 करोड़ रुपये की लागत से बने 'चंद्रयान-2' का प्रक्षेपण किया।

स्वदेशी तकनीक से निर्मित 'चंद्रयान-2' में कुल 13 पेलोड हैं।

आठ ऑर्बिटर में, तीन पेलोड लैंडर 'विक्रम' और दो पेलोड रोवर 'प्रज्ञान' में हैं।

लैंडर 'विक्रम' का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया है। दूसरी ओर, 27 किलोग्राम वजनी 'प्रज्ञान' का मतलब संस्कृत में 'बुद्धिमता' है। ऑर्बिटर, चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा 'चंद्रयान-2' के लैंडर 'विक्रम' के बीच संकेत प्रसारित करेगा।

लैंडर 'विक्रम' को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'प्रज्ञान' नाम का रोवर कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स) संचालित 6-पहिया वाहन है। इसरो के अनुसार चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव रोचक जगह है जहां उत्तरी ध्रुव के विपरीत अंधकार छाया रहता है। ■

नयी वेतन संहिता से 50 करोड़ कामगारों को लाभ

केंद्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार के अनुसार नयी वेतन संहिता से देश में करीब 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। दरअसल, यह वेतन संहिता एक मील का पत्थर है जो देश के प्रत्येक श्रमिक को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगा।

उन्होंने 14 अगस्त को पुणे में कहा कि नयी वेतन संहिता श्रमिकों, नियोक्ताओं और राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि अति महत्वपूर्ण 'वेतन संहिता विधेयक, 2019' राज्यसभा में 2 अगस्त को पास हो गया था। इसके पक्ष में 85 सदस्यों और विरोध में 8 ने मतदान किया। यह विधेयक वेतन, बोनस से जुड़े कानूनों में संशोधन और उनका एकीकरण करता है। लोकसभा में यह विधेयक 30 जुलाई को पास हुआ था।

वेतन के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति समान वेतन का निर्धारण करेगी। इस समिति में मजदूर यूनियन, रोजगार प्रदान करने वाले संगठन तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि आवश्यकता हुई तो समिति एक तकनीकि समिति का भी गठन कर सकती है।

दरअसल, चार संहिताओं में यह पहली संहिता है। चार संहिताएं हैं– वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता। इन संहिताओं को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तैयार किया है। श्रम पर गठित दूसरे राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मंत्रालय ने विभिन्न श्रम कानूनों का इन चार श्रम संहिताओं में समावेश किया है।

केंद्रीय मंत्री श्री गंगवार ने कहा, "अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में यह फैसला लिया गया था कि श्रम से जुड़े कई कानून हैं, इसलिए इन्हें समाहित कर देना चाहिए। इन कानूनों को चार से पांच संहिताओं में समाहित करने का सुझाव दिया गया था।" श्री गंगवार ने कहा कि दुर्भाग्यवश सरकार बदल गई और 10 साल तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि, 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद फिर से यह मुद्दा उठा और इस पूरी प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन होना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि केंद्र न्यूनतम मेहनताना तय करेगी और उसके आधार पर राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन पर फैसला लेंगी और उसे तय करेंगी। हालांकि, यह केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए।

श्री गंगवार ने कहा कि यह कर्मचारियों, नियोक्ताओं और राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इस विधेयक से 50 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। इसमें असगंठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई संहिता श्रम मजदूरी में विसंगतियों को ठीक करेगी। ■

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 10 अगस्त को प्रधान न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 किए जाने संबंधी एक विधेयक पर दस्तखत कर दिया। उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक को इसी सप्ताह संसद की मंजूरी मिली थी।

फिलहाल, शीर्ष न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) समेत कुल 31 पद हैं। कानून लागू होने के बाद सीजेआई को छोड़कर 33 पद होंगे। शीर्ष न्यायालय में मामलों की बढती संख्या के मद्देनजर न्यायाधीश के पदों की संख्या में इजाफे के लिए विधेयक लाया गया था।

उच्चतम न्यायालय में करीब 60 हजार मामले लंबित हैं। विधि मंत्रालय ने 11 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि शीर्ष अदालत में 59,331 मामले लंबित हैं।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले देश के प्रधान न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण कानून के सवालों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले के लिए जरूरत के मुताबिक संविधान पीठ नहीं गठित हो पा रही। ■

जुलाई, 2019 के दौरान काफी कम हुई महंगाई

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 1.08 प्रतिशत

मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जुलाई, 2019 के दौरान 1.08 प्रतिशत रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 2.02 प्रतिशत थी। इस तरह जुलाई, 2019 के दौरान महंगाई में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 5.27 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति की दर 1.08 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर 3.1 प्रतिशत थी। जुलाई, 2019 के दौरान 'सभी जिंसों' के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्षः 2011-12=100) पिछले महीने के 121.5 अंक (अनंतिम) से 0.2 प्रतिशत घटकर 121.2 अंक (अनंतिम) रह गया।

इस दौरान फल एवं सब्जियों (5%); अंडे, मक्का एवं ज्वार (प्रत्येक 4 प्रतिशत); बाजरा, गेहूं एवं मसाले (प्रत्येक 2 प्रतिशत) और जौ, मूंग, धान, मटर/चावली, रागी एवं अरहर (प्रत्येक 1 प्रतिशत) के दाम बढ़ गए। वहीं, दूसरी ओर इस दौरान समुद्री मछली (7 प्रतिशत), चाय (6 प्रतिशत), पान के पत्ते (5 प्रतिशत), पोल्ट्री चिकन (3 प्रतिशत) और अंतर्देशीय मछली एवं उड़द (प्रत्येक 1 प्रतिशत) के दाम घट गए।

'अखाद्य पदार्थों' के समूह का सूचकांक पिछले महीने के 128.7 अंक (अनंतिम) से 0.1 प्रतिशत बढ़कर जुलाई, 2019 में 128.8 अंक (अनंतिम) हो गया। ऐसा मूंगफली बीज (5%); तिल के बीज एवं कपास बीज (प्रत्येक 3%); पुष्पकृषि (2 प्रतिशत) और पशुचारे, कच्चे रबर एवं अरंडी का बीज (प्रत्येक 1%) के दाम बढ़ने के कारण हुआ। उधर, सोयाबीन, कच्चा जूट, मेस्ता और सूरजमुखी (प्रत्येक 3%),नाइजर सीड (2%) और कच्ची कपास, ग्वार बीज, कुसुम (कार्डी बीज) और अलसी (प्रत्येक 1%) के दाम घट गए।

'खाद्य उत्पादों के विनिर्माण' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 130.4 अंक (अनंतिम) से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 130.9 अंक (अनंतिम) हो गया। ऐसा शीरे के दाम में वृद्धि होने के साथ-साथ प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ (4 प्रतिशत), मैदा (3 प्रतिशत) और गुड़, चावल की भूसी के तेल, सूजी एवं पाउडर मिल्क (प्रत्येक 2 प्रतिशत) और बेकरी उत्पादों, घी, गेहूं का आटा, शहद, सरसों तेल, सूरजमुखी तेल एवं नमक (प्रत्येक 1 प्रतिशत) के दाम बढ़ने के कारण हुआ। ■

वर्ष 2016 की तुलना में 2018 में पराली जलाने की घटनाओं में 41 प्रतिशत की कमी

कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय योजना के सफल क्रियान्वयन से वर्ष 2018 में धान की पराली को जलाने की घटनाओं में 2017 की तुलना में 15 प्रतिशत और 2016 की तुलना में 41 प्रतिशत की कमी आई।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने 13 अगस्त को बताया कि 2018 में हरियाणा और पंजाब के 4500 से अधिक गांव पराली जलाने से मुक्त घोषित किए गए हैं। इस दौरान पराली जलाने की एक भी घटना नहीं हुई है।

डॉ. महापात्रा ने कहा की केन्द्र सरकार ने 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए कुल 1151.80 करोड़ रुपये की प्रावधान किया है, ताकि वायु प्रदूषण को दूर किया जा सके और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनों पर सहायता प्रदान की जा सके। योजना लागू होने के एक साल के भीतर 500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करते हुए भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों के 8 लाख हेक्टेयर जमीन पर सीडर प्रौद्योगिकी अपनाई गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए क्रमशः 269.38 करोड़ रुपये, 137.84 करोड़ रुपये और 148.60 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसी तरह वर्ष 2019-20 के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए क्रमशः 273.80 करोड़ रुपये, 192.06 करोड़ रुपये और 105.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

आईसीएआर इस योजना को 60 कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए लागू कर रहा है, जिनमें से पंजाब के 22, हरियाणा के 14, दिल्ली का 1 और उत्तर प्रदेश के 23 केन्द्र शामिल हैं। बैनर और होर्डिंग के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा गांव स्तर पर 700, 200 किसान गोष्ठियों, 86 किसान मेलों और 250 स्कूलों तथा कॉलेजों के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ■

परानुकरण से राष्ट्र की सृजनात्मक शक्ति समाप्त हो रही है

दीनदयाल उपाध्याय

काम करो और एक मत से विचार करके काम करो, यह अपनी बहुमत से विचार करके तय करो। विरोधी दल ज़रूर चाहिए, एक मत हो गया तो ठीक है, परस्पर विचार विमर्श हो सकता है, विवाद भी हो सकता है और हमेशा हुआ है, परंतु हमारे यहां विरोध के लिए विरोध कभी मान्य नहीं रहा। फिर भी पश्चिम की 'डेमोक्रेसी' तो इसी विरोध की नींव पर खड़ी है। वहां विरोध होना ही चाहिए। जैसा कि उनके विचारकों का कहना है- फुटबॉल का खेल होता है, उसमें दो पार्टियां होनी चाहिए। यदि एक ही पार्टी रही तो फुटबॉल का खेल नहीं हो सकता है। इसीलिए इंग्लैंड में विरोधी दल को 'हिज़ मैजेस्टीज़ व अपोजीशन' कहा है। वहां दो पार्टियां हैं, 'एक कंजर्वेटिव' और दूसरी 'लिबरल।' एक अंग्रेज़ ने कहा कि इंग्लैंड में जो कोई भी पैदा होता है, वह खटाक से या तो लिबरल पैदा होता है या कंजर्वेटिव। यह वहां के लिए ठीक भी है, क्योंकि वहां की राजनीति ही ऐसी है। वे कहते हैं कि प्रत्येक लड़का और लड़की जन्मजात टॉरी है अथवा कंजर्वेटिव।'

हमारी पद्धति कहती है, हाथ जोड़कर प्रणाम करो, पर अंग्रेज़ी पद्धति में पला आदमी खटाक से अपना हाथ बढ़ा देता है, लगता है हाथ जोड़कर प्रणाम करने में उसे कुछ अटपटा लगता है। (बहुत सी आम सभाओं में यदि प्रमुख' पुरुष हैं, तब तो काम चल जाता है, पर यदि महिला हुई तो अंतर्द्वंद्व चलता है। बहुत सी महिलाओं ने तो अपने पतियों के साथ ऐसी सभाओं में जाना छोड़ दिया है, जिससे पति-पत्नी के बीच द्वंद्व पैदा हो गया है। इस प्रकार के झगड़े घर-घर में, राष्ट्र में सब जगह दिखाई दे रहे हैं।) ऐसी स्थिति में हमें यह निश्चय करना ही होगा कि हम परकीय का अनुकरण नहीं करेंगे। यह आवश्यक है। पहले जो कुछ हमने सोचा, वह बुद्धिमत्ता नहीं थी, पिछड़ापन था और आज हमें जो बुद्धिमत्ता प्राप्त है, वह पिछले सौ सवा सौ वर्षों के अंग्रेज़ी शिक्षा के संस्कारों का परिणाम है, इस बात को दिमाग़ से निकालना होगा। आजकल अच्छा और बुरा इतना सीधा-सादा हो गया है कि उसके विवेचन में कोई देरी नहीं लगती। जो बाहर का है, वह अच्छा है, अंग्रेज़ी पद्धति का होगा वह अच्छा, बाक़ी सब बुरा। एक स्थान पर एक सज्जन मिले। कहने लगे, 'अमुक व्यक्ति बड़ा गंवार है।' मैंने कहा, कैसे तो कहने लगे 'गंवार का अर्थ गांव में रहने वाला। वहीं की पद्धति का पालन करने वाला। घर में भोजन करता हो तो ज़मीन पर बैठकर, थूकने की इच्छा हुई तो उठकर दूर जाकर थूकता है।' मैंने कहा कि आपको थूकने की इच्छा हुई तो रूमाल में थूक कर उसे जेब में रख लेते हैं। आप उसको गंवार कहते हैं, स्वयं बड़े सभ्य हैं। बड़े हाइजीनिक हैं। स्वच्छता का विचार करनेवाले हैं। यह है आज की विचार करने की पद्धति।

कुछ लोग कहते हैं कि आख़िर युगधर्म का भी तो विचार करना चाहिए। यह बात सच है कि बिना काल का विचार किए काम नहीं चलता। अपने यहां भी जहां धर्म का विचार किया गया, वहां काल का भी विचार किया गया है। जाड़े के दिनों में मलमल का कुरता पहनने से क्या दशा होगी, यह स्पष्ट है। काल का विचार हम भी करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि आख़िर युगधर्म का भी तो विचार करना चाहिए। यह बात सच है कि बिना काल का विचार किए काम नहीं चलता। अपने यहां भी जहां धर्म का विचार किया गया, वहां काल का भी विचार किया गया है। जाड़े के दिनों में मलमल का कुरता पहनने से क्या दशा होगी, यह स्पष्ट है। काल का विचार हम भी करते हैं। हम विचार करें, युगधर्म के नाम पर परिचय की चीजें, जिन पर 'मॉर्डन का लेबल' लगा रहता है, उनका मतलब क्या है? क्या अमरीका में जो हो वही 'मॉर्डन' है? हमारे यहां भी तो कुछ चीजें हो सकती हैं। मंगल अवसर पर केक काटने से प्रसन्न क्यों? उद्घाटन के समय फीता काटना ही आधुनिकता कैसे? यह 'मॉडर्निज्म' नहीं 'वेस्टर्निज्म' है। हम जब पूजन करें तो दकियानूसी और फीता काटें तो मॉर्डन। हमें इस ग़लत विचार प्रवाह को सही दिशा देनी होगी।

हम माडर्निज्म का विचार करें। अपनी भी तो एक जीवन पद्धति है। यदि हम अपने जीवन की रक्षा, उसका विकास करना चाहते हैं तो बाहर की चीजें भले ही मॉडर्न हों, उन्हें हटाकर अपने आधार पर विचार करना होगा। बाहर की चीज़ों से अपने जीवन की शक्तियां कुंठित होती हैं। उनका विकास रुक जाता है। जब तक जीवन की सारी

शक्तियों के विकास का मार्ग नहीं खुलता तब तक व्यावहारिक रूप से बाहर के अनुकरण से हमें लाभ नहीं होगा। अंग्रेज़ किसी किसान या मज़दूर को अपना काम करने से रोकते नहीं और आज वह अंग्रेज़ भी नहीं रहे। हमारी स्वतंत्रता के मार्ग में रही-सही बातें भी समाप्त हो गईं। अब हम यह सोचें कि पिछले बारह-तेरह वर्षों में देश के चालीस करोड़ लोगों ने देश के विकास में क्या योगदान दिया है? ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब अब भी अंग्रेज़ियत प्रकट होती है। मेरे एक परिचित मित्र संस्कृत के विद्वान् और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी। उन्हें कार्य करने में पग-पग पर कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि यहां के विचारों में अंग्रेजियत भरी है। इस अंग्रेज़ियत ने समाज के सारे वातावरण में भ्रम पैदा कर दिया है, यह राष्ट्र की उन्नति में बाधा पैदा कर रही है। यदि हम अपना सारा जीवन भुलाकर बाह्य जीवन यहां ले आए तो यह राष्ट्र का दुर्दैव होगा। अफ्रीका की कुछ जातियों को अंग्रेजों ने ईसाई बनाया, उन्हें अपने कपड़े पहनना सिखाया, यानी सभ्यता सिखाई और आज वह जाति समाप्त हो रही है। उस जाति की धीरे-धीरे सृजनात्मक शक्ति समाप्त हो रही है। दुनिया में बड़ी-बड़ी जातियां इसी प्रकार समाप्त हो गईं। हम भी यदि अपना संपूर्ण जीवन बाहर से लाएं तो प्रगति नहीं कर सकेंगे, समाप्त हो जाएंगे। अनुकरण से विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि हमें संपूर्ण जीवन का आधार ही बनाना हो तो स्वाभिमान का आधार चाहिए। ■

(पाञ्चजन्य, अक्तूबर 3, 1960)

सरकार सस्ती दर पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 30,000 रुपये की दर से लिए जाने वाले अनिवार्य पट्टा किराये में छूट देने का फैसला किया। एक समीक्षा बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 30,000 रुपये की दर से पट्टा किराया लेने की स्थिति में छूट देने का फैसला किया।

श्री जावडेकर ने 22 अगस्त को कहा कि उम्मीद है कि इस कदम से पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा और सस्ती दरों पर पवन ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण मंत्री ने कहा, 'सरकार नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करके ऊर्जा की अधिकतम जरूरत को पूरा करना चाहती है ताकि एक निश्चित समय पर स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न नीतियों और नियमों में लगातार सुधार किया जा रहा है।'

इस समय वन भूमि पर पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण और निर्धारित वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए अनिवार्य शुल्क अदा करना आवश्यक है। अनिवार्य शुल्क के अलावा, पवन ऊर्जा कंपनियों को 30,000 रुपये प्रति मेगावाट की दर से पट्टा किराया की अतिरिक्त कीमत अदा करनी पड़ती थी।

यह अतिरिक्त कीमत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा और पनबिजली परियोजना के लिए अनिवार्य नहीं है। पवन

ऊर्जा के जरिये स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए अतिरिक्त कीमत से उपभोक्ता के स्तर पर बिजली की प्रति इकाई कीमत बढ़ जाती है।

इस तरह की परियोजनाओं को बढ़ावा देने से अंतरराष्ट्रीय समझौतों की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। वर्ष 2015 में पेरिस में की गई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में 2030 तक नवीकरणीय संसाधनों से 40 प्रतिशत बिजली बनाने की बात कही गई थी। इस समय भारत लक्ष्य से आगे निकल चुका है और यह सुनिश्चित करने के लिए सही रास्ते पर चल रहा है कि 2030 तक हमारी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हो। ■

मेरे अटल जी

नरेन्द्र मोदी

अटल जी अब नहीं रहे। मन नहीं मानता। अटल जी, मेरी आंखों के सामने हैं, स्थिर हैं। जो हाथ मेरी पीठ पर धौल जमाते थे, जो स्नेह से, मुस्कराते हुए मुझे अंकवार में भर लेते थे, वे स्थिर हैं। अटल जी की ये स्थिरता मुझे झकझोर रही है, अस्थिर कर रही है। एक जलन सी है आंखों में, कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहा। मैं खुद को बार-बार यकीन दिला रहा हूं कि अटल जी अब नहीं हैं, लेकिन ये विचार आते ही खुद को इस विचार से दूर कर रहा हूं। क्या अटल जी वाकई नहीं हैं? नहीं। मैं उनकी आवाज अपने भीतर गूंजते हुए महसूस कर रहा हूं, कैसे कह दूं, कैसे मान लूं, वे अब नहीं हैं।

वे पंचतत्व हैं। वे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सबमें व्याप्त हैं, वे अटल हैं, वे अब भी हैं। जब उनसे पहली बार मिला था, उसकी स्मृति ऐसी है जैसे कल की ही बात हो। इतने बड़े नेता, इतने बड़े विद्वान। लगता था जैसे शीशे के उस पार की दुनिया से निकलकर कोई सामने आ गया है। जिसका इतना नाम सुना था, जिसको इतना पढ़ा था, जिससे बिना मिले, इतना कुछ सीखा था, वो मेरे सामने थे। जब पहली बार उनके मुंह से मेरा नाम निकला तो लगा, पाने के लिए बस इतना ही बहुत है। बहुत दिनों तक मेरा नाम लेती हुई उनकी वह आवाज मेरे कानों से टकराती रही। मैं कैसे मान लूं कि वह आवाज अब चली गई है।

कभी सोचा नहीं था, कि अटल जी के बारे में ऐसा लिखने के लिए कलम उठानी पड़ेगी। देश और दुनिया अटल जी को एक स्टेट्समैन, धारा प्रवाह वक्ता, संवेदनशील कवि, विचारवान लेखक, धारदार पत्रकार और विजनरी जन नेता के तौर पर जानती है, लेकिन मेरे लिए उनका स्थान इससे भी ऊपर का था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे उनके साथ बरसों तक काम करने का अवसर मिला, बल्कि मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्शों-मूल्यों पर जो छाप उन्होंने छोड़ी, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया, उसने मुझे गढ़ा है, हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है।

हमारे देश में अनेक ऋषि, मुनि, संत आत्माओं ने जन्म लिया है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक की विकास यात्रा के लिए भी असंख्य लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा और 21वीं सदी के सशक्त, सुरक्षित भारत के लिए अटल जी ने जो किया, वह अभूतपूर्व है।

उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था- बाकी सब का कोई महत्त्व नहीं। इंडिया फर्स्ट –भारत प्रथम, ये मंत्र वाक्य उनका जीवन ध्येय था। पोखरण देश के लिए जरूरी था तो चिंता नहीं की प्रतिबंधों और आलोचनाओं की, क्योंकि देश प्रथम था। सुपर कंप्यूटर नहीं मिले, क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिले तो परवाह नहीं, हम खुद बनाएंगे, हम खुद अपने दम पर अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक कुशलता के बल पर असंभव दिखने वाले कार्य संभव कर दिखाएंगे और ऐसा किया भी। दुनिया को चकित किया। सिर्फ एक ताकत उनके भीतर काम करती थी- देश प्रथम की जिद।

काल के कपाल पर लिखने और मिटाने की ताकत, हिम्मत और चुनौतियों के बादलों में विजय का सूरज उगाने का चमत्कार उनके सीने में था, तो इसलिए क्योंकि वह सीना देश प्रथम के लिए धड़कता था। इसलिए हार और जीत उनके मन पर असर नहीं करती थी। सरकार बनी तो भी, सरकार एक वोट से गिरा दी गयी तो भी, उनके स्वरों में पराजय को भी विजय के ऐसे गगनभेदी विश्वास में बदलने की ताकत थी कि जीतने वाला ही हार मान बैठे।

अटल जी कभी लीक पर नहीं चले। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नए रास्ते बनाए और तय किए। "आंधियों में भी दीये जलाने" की क्षमता उनमें थी। पूरी बेबाकी से वे जो कुछ भी बोलते थे, सीधा जनमानस के हृदय में उतर जाता था। अपनी बात को कैसे रखना

है, कितना कहना है और कितना अनकहा छोड़ देना है, इसमें उन्हें महारत हासिल थी।

राष्ट्र की जो उन्होंने सेवा की, विश्व में मां भारती के मान-सम्मान को उन्होंने जो बुलंदी दी, इसके लिए उन्हें अनेक सम्मान भी मिले। देशवासियों ने उन्हें भारत रत्न देकर अपना मान भी बढ़ाया। लेकिन वे किसी भी विशेषण, किसी भी सम्मान से ऊपर थे।

जीवन कैसे जीया जाए, राष्ट्र के काम कैसे आया जाए, यह उन्होंने अपने जीवन से दूसरों को सिखाया। वे कहते थे, "हम केवल अपने लिए ना जीएं, औरों के लिए भी जीएं...हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी।"

देश के गरीब, वंचित, शोषित के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वे जीवन भर प्रयास करते रहे। वे कहते थे "गरीबी, दरिद्रता गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि यह विवशता है, मजबूरी है और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता।" करोड़ों देशवासियों को इस विवशता से बाहर निकालने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। गरीब को अधिकार दिलाने के लिए देश में आधार जैसी व्यवस्था, प्रक्रियाओं का ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण, हर गांव तक सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज, देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्पों से जुड़ा था।

आज भारत जिस टेक्नोलॉजी के शिखर पर खड़ा है उसकी आधारशिला अटल जी ने ही रखी थी। वे अपने समय से बहुत दूर तक देख सकते थे - स्वप्नद्रष्टा थे लेकिन कर्मवीर भी थे। कवि हृदय, भावुक मन के थे तो पराक्रमी सैनिक मन वाले भी थे। उन्होंने विदेश की यात्राएं कीं। जहां-जहां भी गए, स्थाई मित्र बनाये और भारत के हितों की स्थाई आधारशिला रखते गए। वे भारत की विजय और विकास के स्वर थे।

अटल जी का प्रखर राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए समर्पण करोड़ों देशवासियों को हमेशा से प्रेरित करता रहा है। राष्ट्रवाद उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि जीवन शैली थी। वे देश को सिर्फ एक भूखंड, ज़मीन का टुकड़ा भर नहीं मानते थे, बल्कि एक जीवंत, संवेदनशील इकाई के रूप में देखते थे। "भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है।" यह सिर्फ भाव नहीं, बल्कि उनका संकल्प था, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। दशकों का सार्वजनिक जीवन उन्होंने अपनी इसी सोच को जीने में, धरातल पर उतारने में लगा दिया। आपातकाल ने हमारे लोकतंत्र पर जो दाग लगाया था उसको मिटाने के लिए अटल जी के प्रयास को देश हमेशा याद रखेगा।

जीवन कैसे जीया जाए, राष्ट्र के काम कैसे आया जाए, यह उन्होंने अपने जीवन से दूसरों को सिखाया। वे कहते थे, "हम केवल अपने लिए ना जीएं, औरों के लिए भी जीएं...हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी।"

राष्ट्रभक्ति की भावना, जनसेवा की प्रेरणा उनके नाम के ही अनुकूल अटल रही। भारत उनके मन में रहा, भारतीयता तन में। उन्होंने देश की जनता को ही अपना आराध्य माना। भारत के कण-कण, कंकर-कंकर, भारत की बूंद-बूंद को, पवित्र और पूजनीय माना।

जितना सम्मान, जितनी ऊंचाई अटल जी को मिली उतना ही अधिक वह ज़मीन से जुड़ते गए। अपनी सफलता को कभी भी उन्होंने अपने मस्तिष्क पर प्रभावी नहीं होने दिया। प्रभु से यश, कीर्ति की कामना अनेक व्यक्ति करते हैं, लेकिन ये अटल जी ही थे जिन्होंने कहा,

"हे प्रभु! मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना"

अपने देशवासियों से इतनी सहजता और सरलता से जुड़े रहने की यह कामना ही उनको सामाजिक जीवन के एक अलग पायदान पर खड़ा करती है।

वे पीड़ा सहते थे, वेदना को चुपचाप अपने भीतर समाये रहते थे, पर सबको अमृत देते रहे- जीवन भर। जब उन्हें कष्ट हुआ तो कहने लगे- "देह धरण को दंड है, सब काहू को होये, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूरख भुगते रोए।" उन्होंने ज्ञान मार्ग से अत्यंत गहरी वेदनाएं भी सहन कीं और वीतरागी भाव से विदा ले गए।

यदि भारत उनके रोम-रोम में था तो विश्व की वेदना उनके मर्म को भेदती थी। इसी वजह से हिरोशिमा जैसी कविताओं का जन्म हुआ। वे विश्व नायक थे। मां भारती के सच्चे वैश्विक नायक। भारत की सीमाओं के परे भारत की कीर्ति और करुणा का संदेश स्थापित करने वाले आधुनिक बुद्ध।

कुछ वर्ष पहले लोकसभा में जब उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित किया गया था तब उन्होंने कहा था, "यह देश बड़ा अद्भुत है, अनूठा है। किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाकर अभिवादन किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा सकता है।"

अपने पुरुषार्थ को, अपनी कर्तव्यनिष्ठा को राष्ट्र के लिए समर्पित करना उनके व्यक्तित्व की महानता को प्रतिबिंबित करता है। यही सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए उनका सबसे बड़ा और प्रखर संदेश है। देश के साधनों, संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए, हमें अब अटल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों का भारत बनाना है।

नए भारत का यही संकल्प, यही भाव लिए मैं अपनी तरफ से और सवा सौ करोड़ देशवासियों की तरफ से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

(यह लेख श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर अगस्त 2018 में प्रकाशित हुआ था।)

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन

(2 जून, 1930 – 21 अगस्त, 2019)

भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर का 21 अगस्त को भोपाल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्री गौर 2004-2005 के दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा वे भोपाल की गोविंदपुरा सीट से लगातार 10 बार विधायक रहे।

प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** ने श्री गौर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, "बाबूलाल गौर जी का लम्बा राजनीतिक जीवन जनता-जनार्दन की सेवा में समर्पित था। जनसंघ के समय से ही उन्होंने पार्टी को मज़बूत और लोकप्रिय बनाने के लिए मेहनत की। मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में मध्यप्रदेश के विकास के लिए किए गए उनके कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे।"

उन्होंने कहा, ''बाबूलाल गौर जी के निधन से गहरा दुःख हुआ। ईश्वर शोक संतप्त परिवार को दुःख की इस घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शान्ति!"

केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष **श्री अमित शाह** ने श्री बाबूलाल गौर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की सेवा एवं राष्ट्र के विकास के प्रति उनका समर्पण सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। श्री शाह ने ट्वीट किया कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका पूरा जीवन प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित रहा। बाबूलाल गौर जी 'भारतीय मजदूर संघ' के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया जिसके लिए उन्हें 19 माह की जेल भी हुई।

उन्होंने कहा, ''बाबूलाल गौर जी ने 'गोवा मुक्ति आन्दोलन' में भी सक्रीय भूमिका निभाई। मध्यप्रदेश में भाजपा को सशक्त करने और जनता के हितों के लिए उनके संघर्ष सदैव याद किये जायेंगे। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करे। ॐ शांति शांति शांति।"

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष **श्री जगत प्रकाश नड्डा** ने श्री गौर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, "जनसंघ काल के वरिष्ठ नेता, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी के निधन से मन व्यथित है। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मध्यप्रदेश के विकास को समर्पित किया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को दुःख सहने की शक्ति दें। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री **श्री शिवराज सिंह चौहान** ने कहा, "मध्यप्रदेश की राजनीति में एक युग की समाप्ति। भाजपा मध्यप्रदेश के आधार स्तंभ, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मार्गदर्शक व जन-जन के नेता बाबूलाल गौर के निधन से दुःखी हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें व परिजनों को इस गहन दुःख को सहने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति।"

मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष **श्री राकेश सिंह** ने ट्वीट कर लिखा, ''अत्यंत दुःख की बात है कि हमारे मार्गदर्शक भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल जी गौर अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान प्रदान करे।''

जीवन परिचय

2 जून 1930 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पैदा होने होने वाले श्री बाबूलाल गौर का भाजपा के नेता के रूप में मध्यप्रदेश की राजनीति में प्रमुख स्थान रहा। श्री गौर शिवराज के मंत्रिमंडल में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री रहे। श्री गौर पहली बार 1974 में भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में विधायक चुने गए। उन्होंने 1977 में गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वर्ष 2013 तक वहां से लगातार चुनाव लड़े और जीते भी।

बीए, एलएलबी श्री गौर 1990 से 1992 तक मध्यप्रदेश के स्थानीय शासन, विधि एवं विधायी कार्य, संसदीय कार्य, जनसंपर्क, नगरीय कल्याण, शहरी आवास तथा पुनर्वास एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री रहे। वे 2002 से 2003 तक मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे।

श्री बाबूलाल गौर सन् 1946 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने दिल्ली तथा पंजाब आदि राज्यों में आयोजित सत्याग्रहों में भी भाग लिया। श्री गौर आपातकाल के दौरान 19 माह जेल में भी रहे।

सक्रिय राजनीति में आने से पहले बाबूलाल गौर ने भोपाल की कपड़ा मिल में नौकरी की थी और श्रमिकों के हित में अनेक आंदोलनों में भाग लिया था। वे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। ■

मजबूत इच्छाशक्ति से बदलाव लाते मोदी

अमित शाह

आजादी के बाद हुए 17 लोकसभा चुनावों में देश ने 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। निःसंदेह इन सभी सरकारों ने राष्ट्र निर्माण में अपने विवेक के अनुसार कुछ न कुछ किया, परंतु ऐसी सरकारें विरली रहीं जो दूरगामी परिणाम लाने वाले काम कर सकीं। अपने 55 वर्षो के शासन में कांग्रेस को आठ बार पूर्ण बहुमत वाला जनादेश मिला, लेकिन उसने शायद दस काम भी ऐसे नहीं किए जिनसे देश को निर्णायक दिशा मिली हो। हालांकि वाजपेयी सरकार ने अल्पकाल में कई बड़े काम करने के प्रयास किए, परंतु बहुमत के अभाव में उनका प्रभाव सीमित रहा। देश में पहली बार 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोदीजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में परिवर्तन की जो बयार बहती दिख रही है उसके पीछे मजबूत नेतृत्व और विकासोन्मुख नीतियां हैं। मोदी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में ही दर्जनों ऐसे काम किए हैं जिनसे न केवल सामान्य जन के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार आया है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी विश्व में फिर से स्थापित हुई है। मोदीजी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अतुलनीय दृढ़ इच्छाशक्ति है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण राज्यसभा में संख्याबल न होने के बावजूद अनुच्छेद-370 और 35-ए को समाप्त करना रहा। इन दोनों अनुच्छेदों के कारण कश्मीर देश की विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया जिससे वहां आतंकी और अलगाववादी शक्तियां फल-फूल रही थीं। आतंकी हिंसा से 41 हजार कश्मीरी मौत का शिकार हुए, केंद्र से भेजी जाने वाली विकास की राशि गिने चुने लोगों की जेब भरती रही और कई पीढ़ियां गरीबी और अशिक्षा का दंश झेलती रहीं। तुष्टीकरण की राजनीति और इच्छाशक्ति की कमी के कारण किसी भी नेता या सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद-370/35-ए से मुक्ति दिलाने का साहस नहीं किया। यह एक देश एक संविधान के सपने को पूरा करने की मोदीजी की मजबूत इच्छाशक्ति ही थी कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद-370/35-ए से मुक्ति मिल सकी।

यह भी मोदीजी की दृढ़ इच्छाशक्ति ही है कि वह विषम राजनीतिक परिस्थितियों में भी अनेक कठिन फैसले ले सके। कभी असंभव से दिखने वाले सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक जैसे फैसले लेना मोदीजी को देश का अब तक का सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाला प्रधानमंत्री साबित करता है। स्वतंत्रता के बाद देश की सरकारें अमीर-गरीब, शहर-गांव, कृषि-उद्योग जैसे अनेक विरोधाभासों से ग्रस्त रहीं। कुछ शक्तियों ने ऐसा वैचारिक वातावरण बना दिया था जिससे ये भ्रामक द्वंद्व देश के विकास में एक बड़ी बाधा बन गए। नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तत्काल इस द्वंद्व को खत्म किया। अमीर और गरीब की खाई पाट कर सबको एक साथ लेकर चलने की नीति प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन से स्पष्ट होती है कि देश में सिर्फ दो वर्ग हैं, एक गरीब और दूसरा गरीबी हटाने वाला।

मोदी सरकार की नीतियों में गरीबों के कल्याण के प्रति चिंता और अन्तोदय का भाव स्पष्ट नजर आता है। सामान्य जन के जीवन में बदलाव लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। जनधन, मुद्रा, सौभाग्य, स्वच्छ भारत, श्रमयोगी मानधन पेंशन, किसान पेंशन और लघु व्यापारी मानधन जैसी दर्जनों योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आमजन के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें नीम कोटेड यूरिया लाना, समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना वृद्धि, समर्थन मूल्य दायरे का विस्तार, यूरिया सब्सिडी में वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि प्रमुख हैं। तीन तलाक उन्मूलन, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे निर्णयों के जरिये भी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। मोदी सरकार का मानना है कि व्यवसायी के विकास के बिना गरीबों का कल्याण संभव नहीं है। मोदीजी ने वेल्थ क्रिएटर के महत्व को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है। चरमराई बैंकिंग प्रणाली के पुनरुत्थान, भ्रष्टाचार पर प्रहार के कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, कानूनों के सरलीकरण, जीएसटी इत्यादि जैसे अनेक प्रयास व्यापार को सुगम बना रहे हैं और भारत आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन कर पांच टिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। करदाताओं की संख्या और कर प्राप्ति में जिस तरह वृद्धि हुई है वह मोदी सरकार पर विश्वास और देश के विकास में भागीदारी का प्रतीक है।

पाकिस्तान की आतंकी नीतियों का

जवाब देने के लिए जब देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तब एक तरफ दुनिया के प्रभावी देश भारत के साथ थे तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क अलग-थलग पड़ा हुआ था। कश्मीर के मुद्दे पर भी स्थिति वही है। विश्व पटल पर भारत की ऊंची होती साख का एक और उदाहरण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण के मुद्दे पर विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। आज भारत अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण और एक बार में सर्वाधिक सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के कीर्तिमान ने भी देश का अंतरराष्ट्रीय गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की मंशा और नीति, दोनों स्पष्ट हैं। जहां सेना के आधुनिकीकरण का काम जारी है वहीं अंतरिक्ष में एंटी सेटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर यह सरकार जल, थल और नभ के साथ-साथ अंतरिक्ष तक जुटी हुई है। सेना के तीनों अंगों में समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने का फैसला भी ले लिया गया है। मोदी सरकार ने सैनिकों की वर्षो से लंबित ओआरओपी की मांग को भी पूरा करके उनके मनोबल को बढ़ाया।

मोदी सरकार की कार्य पद्धति का बारीकी से मूल्यांकन करें तो ऐसे अनेक कदम नजर आएंगे, जिन पर कभी किसी सरकार ने कदम उठाना तो दूर, सोचा तक नहीं था। नरेन्द्र मोदी ने सत्ता की परवाह किए बगैर देशहित को ध्यान में रखते हुए कठिन और मूलभूत परिवर्तन लाने वाले साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो आमजन के हित में हों और जरूरी नहीं कि वह लोक लुभावने और देखने में अच्छे लगने वाले हों। इस सरकार ने सिद्ध किया है कि जब देशहित में कठिन निर्णय लिए जाते हैं तो जनता भी समर्थन देने में पीछे नहीं हटती। इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण 2019 के आम चुनाव में नरेन्द्र मोदी का 2014 के जनादेश से बड़े जनादेश के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनना है। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री हैं)
(साभार- दैनिक जागरण)

भारत एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्रः राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 16 अगस्त को पोखरण का दौरा किया, जहां भारत ने 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया था। रक्षामंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। यह देश के नागरिक के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्र अटल जी की महानता के प्रति हमेशा ऋणी रहेगा। रक्षामंत्री ने कहा कि पोखरण भारत को परमाणु शक्ति बनाने और 'पहला प्रयोग नहीं' के लिए अटल जी के दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने इस सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया है। भविष्य में क्या होगा, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

ट्वीट संदेशों की एक श्रृंखला में श्री राजनाथ सिंह ने अटल जी को स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख राजनेता बताया और कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें पोखरण में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ है। ■

सुषमा स्वराज ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सिद्ध करके दिखाया: नरेन्द्र मोदी

भाजपा की वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने विश्व बंधुत्व की भावना के अनुरुप विदेश मंत्रालय की कार्यशैली में मानवीय पहलू को जोड़ा तथा संकटग्रस्त लोगों की हरसंभव मदद की। गत 13 अगस्त को नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष व गृहमंत्री श्री अमित शाह, रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम नेताओं और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के नेताओं ने श्रीमती सुषमा स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज की राजनीति में ऐसे लोगों का बोलबाला है जो लोगों को खुश करने के लिए मुंहदेखी या खुशामद की बात करते हैं। श्रीमती सुषमा का व्यक्तित्व इससे अलग था। वह अपनी बात पूरी दृढ़ता से कहती थीं, भले ही वह किसी को अच्छी लगे या बुरी। अपनी बात कहने में वह कभी संकोच नहीं करती थीं।

श्री मोदीजी ने बतौर विदेश मंत्री उनके कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि सुषमाजी के कार्यकाल में विदेश मंत्रालय का मानवीय चेहरा प्रभावी ढंग से उभरकर सामने आया। उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए विश्वभर में फैले भारतीय समुदाय के लोगों के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विदेश मंत्रालय के जरिए सिद्ध करके दिखाया। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा के कार्यकाल में पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या 77 से 505 हुई। इससे पता चलता है कि उन्हें लोगों की कितनी परवाह थी। श्री मोदी ने दिवंगत नेता से जुड़े संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि सुषमाजी जब भी मुझसे मिलती थीं तो जय श्रीकृष्ण कहती थीं और मैं उन्हें द्वारिकाधीश कहता था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी काम मिले, उसे जी-जान से करना और व्यक्तिगत जीवन में बड़ी ऊंचाई मिलने के बाद भी अहं न रखना, ये कार्यकर्ताओं के लिए सुषमा जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है। श्री मोदी ने एक और संस्मरण का जिक्र करते हुए कहा कि 'मैं और वेंकैयाजी सुषमाजी के पास गए और उन्हें कर्नाटक से चुनाव लड़ने के लिए मनाया, उस चुनाव का परिणाम निश्चित था, लेकिन उन्हें चुनौतियों का सामना करना पसंद था। उन्होंने कहा कि सुषमाजी का भाषण प्रभावी होने के साथ-साथ, प्रेरक भी होता था। सुषमाजी के वक्तव्य में विचारों की

गहराई हर कोई अनुभव करता था, तो अनुभव की ऊंचाई भी हर पल नए मानक पार करती थी। ये दोनों होना एक साधना के बाद ही हो सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई मंत्री या सांसद जब अपने पद पर नहीं रहता है, लेकिन सरकार को उसका मकान खाली कराने के लिए सालों तक नोटिस भेजनी पड़ती है। कभी कोर्ट-कचहरी तक होती है। किंतु सुषमाजी ने चुनाव नतीजे आने के बाद पहला काम मकान खाली करके अपने निजी निवास स्थान पर वो पहुंच गईं।

राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि सुषमा स्वराजजी के जाने से न केवल भाजपा बल्कि समग्र देश के मानचित्र पर एक रिक्तता जो खड़ी हुई है, उसकी भरपाई लंबे अर्से तक नहीं हो पाएगी। वह ओजस्वी वक्ता, जागरूक सांसद, कुशल प्रशासक और विपक्ष की नेता के नाते जनता की आवाज को मुखर करने में संसद के अंदर कभी कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग को जनता के साथ जोड़ना सुषमाजी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। विश्व भर में कोई भी भारतीय कहीं भी हो, वो जब भी उन्हें ट्वीट करता था तो उसे हमेशा उनका जवाब और सहायता मिलती थी।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा की नेत्री के रूप में लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के विकास और सफल यात्रा में जो योगदान दिया है, उसे सभी भाजपा कार्यकर्ता सदैव याद रखेंगे और देश की संसद में उनकी आवाज हमेशा-हमेशा गूंजती रहेगी।

वरिष्ठ नेता और रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुषमा स्वराज जन-मन की नेता थीं। उन्होंने लोगों का दिल जीता था। वह हमेशा अंतर्मन से बोलती थीं।

सुषमाजी ने बहुत से काम ऐसे किए जिससे उन्होंने राजनीति और सरकार में एक अमिट छाप छोड़ी। हम सभी ने एक प्रखर नेता, ओजस्वी वक्ता और ममतायुक्त व्यक्तित्व को खो दिया है।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने कहा कि सुषमाजी ने बहुत से काम ऐसे किए जिससे उन्होंने राजनीति और सरकार में एक अमिट छाप छोड़ी। हम सभी ने एक प्रखर नेता, ओजस्वी वक्ता और ममतायुक्त व्यक्तित्व को खो दिया है। उनके शब्दों में एक धार थी और तर्कपूर्ण तरीके से संसदीय सीमा में बात करने में उन्हें महारथ हासिल थी।

प्रार्थना सभा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान, संत अवधेशानंद गिरी महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी, सांसद सतीश चंद्र मिश्रा, पूर्व सांसद श्री शरद यादव, सांसद श्री सुखबीर सिंह बादल, सांसद सुश्री अनुप्रिया पटेल सहित अनेक नेतागणों ने भाग लिया। ■

'अटलजी ने शुचिता एवं सुशासन की राजनीति को बढ़ावा दिया'

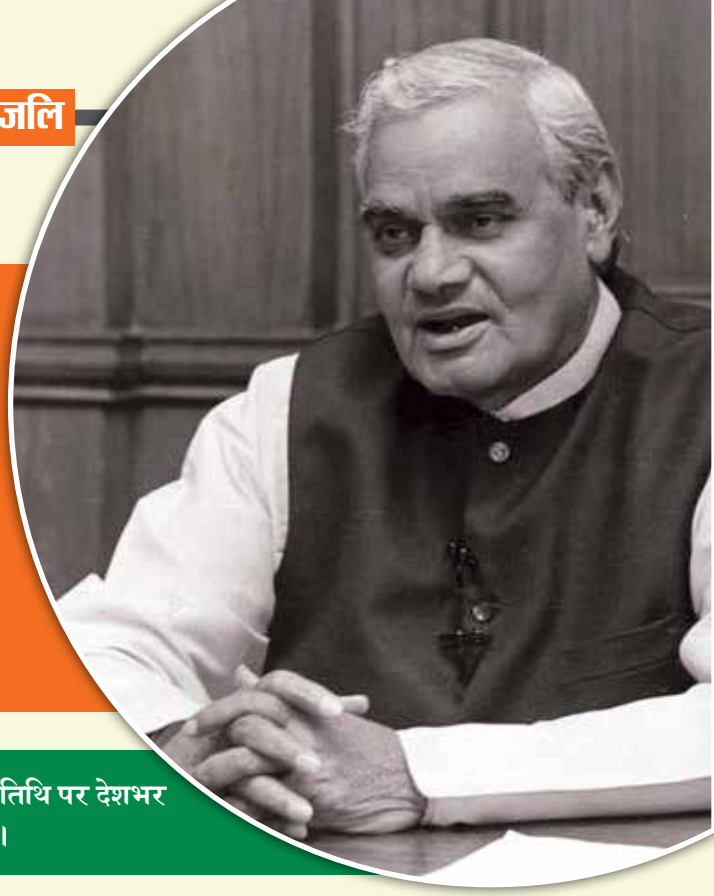

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर देशभर में भाजपा सहित अनेक राजनैतिक दलों के नेताओं ने उन्हें याद किया।

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर 16 अगस्त को नई दिल्ली स्थित समाधि पर जाकर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

दिवंगत वाजपेयी का पिछले साल 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। राष्ट्रपति श्री कोविंद, प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री अमित शाह दिवंगत वाजपेयी के स्मारक स्थल 'सदैव अटल' गये और श्रृद्धा सुमन अर्पित किए और प्रार्थना सभा में शामिल हुए।

वहीं, भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष, असंख्य कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक एवं हमारे प्रेरणा स्रोत भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। पार्टी ने एक वीडियो के साथ अन्य ट्वीट में कहा, 'मां भारती को विश्व में गौरवान्वित करने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।' भाजपा ने अपने संस्थापक नेता द्वारा लिखी गईं कुछ कविताएं भी पोस्ट कीं। 'भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। इसका कंकर-कंकर शंकर है, इसका बिन्दु-बिन्दु गंगाजल है। हम जियेंगे तो इसके लिये मरेंगे तो इसके लिये।'

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का 94 वर्ष की आयु

"अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए उनके विचार और शब्द सजीव है। हम हमेशा भारत के विकास में उनके योगदान की सराहना करेंगे।"

— **नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

**"*अटल एक व्यक्ति नहीं...विचार है*
अटल एक जीवन नहीं...संस्कार है
मूल्यों और आदर्श आधारित अपनी राजनीति से भारत में विकास और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले जन-जन के प्रिय भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि वंदन।"**

— **अमित शाह**, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

अटल जी भारतीय लोकतंत्र की उत्कृष्टतम परंपराओं के प्रेरणा पुंज थे, लोकतंत्र की सात्विक मर्यादाओं के मूर्तरूप थे। देश अपने मानवतावादी युगदृष्टा नेता, सहृदय और ओजस्वी शब्दशिल्पी को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता रहेगा। पुण्यात्मा को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।

— **वेंकैया नायडू**, उपराष्ट्रपति

अटलजी भारतीय राजनीति के ऐसे युगपुरूष थे जिन्होंने मूल्यों एवं आदर्शों के साथ शुचिता एवं सुशासन की राजनीति को बढ़ावा दिया। उनका, सबका साथ सबका विश्वास का भाव आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। अटलजी की प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

— **राजनाथ सिंह**, केंद्रीय रक्षा मंत्री

भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के हृदय में विराजमान एवं हम सभी की प्रेरणा स्रोत, सुशासन के प्रणेता, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर 'सदैव अटल' स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी को श्रद्धाजलि अर्पित की।

दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते
टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते।

राष्ट्र सेवा को जीवन का धेय बनाकर अपने जीवन का क्षण-क्षण राष्ट्र एवं संगठन को पूर्णतः समर्पित कर देने वाले आदर्श स्वयंसेवक, समर्पित कार्यकर्ता, कवि, ओजस्वी वक्ता व अद्भुत राजनेता थे हमारे अटल जी।

— **जगत प्रकाश नड्डा**, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

में गत वर्ष 16 अगस्त को निधन हो गया था। श्री वाजपेयी पहली बार 1996 में 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वह 1998-2004 के बीच दो बार प्रधानमंत्री बने।

'सदैव अटल'

'सदैव अटल' समाधि के केंद्रीय मंच में चौकोर और काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के नौ ब्लॉक लगे हैं, जिसके केन्द्र में एक दीया रखा गया है – यह नौ की संख्या नवरसों, नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। नौ चौकोर पत्थरों की इस समाधि का मंच एक गोलाकार कमल के आकार में है। मंच तक चार प्रमुख दिशाओं से पहुंचा जा सकता है। इसके लिए सफेद मिश्रित टाइलों से मार्ग बनाये गए हैं ताकि फर्श गर्म न हो।

समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया था। समाधि के केंद्र में बनाया गया दीया, खम्मम से प्राप्त लैदर फिनिश काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है।

दीये की लौ क्रिस्टल में बनाई गई हैं जिसमें एलईडी लाइटें लगी हैं। अंदरूनी पंखुडियां और बाहरी पंखुडियां और पंखुड़ियों के बीच का स्थान जो बाहरी परिक्रमा का एक हिस्सा है, उसे क्रिस्टल येलो और नियो कॉपर ग्रेनाइट की रंग संरचना में रखा गया है। ■

भूटान के साथ 10 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग के निमंत्रण पर 17-18 अगस्त, 2019 तक भूटान की राजकीय यात्रा की। मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्राओं में से एक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17-18 अगस्त को भूटान की दो दिवसीय सफल यात्रा की। पारो हवाई अड्डे आगमन पर प्रधानमंत्री डॉ. शेरिंग, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने श्री मोदी का औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भूटान नरेश और महारानी को अपनी सुविधानुसार शीघ्र ही भारत की यात्रा का निमंत्रण दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. शेरिंग ने तय मुद्दों के साथ-साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ताओं में मुलाकात की। भूटान राष्ट्रीय असेंबली में नेता प्रतिपक्ष डॉ. पेमा जियामत्शो ने भी प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुलाकात की।

वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समझौतों की उत्कृष्ट स्थिति के बारे में संतोष जाहिर किया जो आपसी विश्वास सम्मान और साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विकासजन्य तथा जन-जन संबंधों द्वारा मजबूत हो रहे हैं।

इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने संबंधों को पोषित करने में भारत और भूटान के क्रमागत नेतृत्व और भूटान के दूरदर्शी सम्राटों द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की। दोनों देशों के संबंध घनिष्ठ पड़ोसियों के बीच मैत्री और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

एक-दूसरे की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों की पुष्टि की और एक-दूसरे की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर घनिष्ठ तालमेल बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोहराया कि भूटान सरकार और भूटान के लोगों की प्राथमिकताओं और इच्छाओं के अनुसार भारत सरकार भूटान की आर्थिक और बुनियादी ढांचा संबंधी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भूटान को मध्यम आय देश की श्रेणी में ले जाने के लिए भूटान की जनता और राज्य को बधाई दी। उन्होंने भूटान के लोगों को भूटान की 'ग्रॉस नेशनल हेप्पीनेस' के विशिष्ट विकास दर्शन के अनुरूप अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यवान पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

प्रधानमंत्री डॉ. शेरिंग ने दिसंबर 2018 की अपनी भारत यात्रा को याद किया। नवम्बर 2018 में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। उन्होंने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना को समर्थन देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने पिछले कई दशकों से भूटान के विकास में भारत के योगदान की सराहना की।

द्विपक्षीय सहयोग पर जोर

दोनों पक्षों ने आपसी लाभदायक द्विपक्षीय सहयोग के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पनबिजली विकास के महत्व पर जोर दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अभी हाल में निर्मित 720 मेगावाट मांगदेछू पनबिजली संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने इस परियोजना के समय पर पूरा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा समर्पण और कुशलता के लिए परियोजना प्राधिकरण एवं प्रबंधन को बधाई दी।

दोनों पक्षों ने अनुभव किया कि इस परियोजना के चालू हो जाने से भूटान में बिजली की पैदावार क्षमता 2000 मेगावाट से पार हो गई है। दोनों नेताओं ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के प्रति संतोष व्यक्त किया और पुनातसांगछू-1, पुनातसांगछू-2 और खोलोंगछू जैसी अन्य परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने सनकोश जलाशय पनबिजली परियोजना पर जारी द्विपक्षीय बातचीत की समीक्षा भी की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पनबिजली क्षेत्र में भारत-भूटान के आपसी सहयोग के पांच दशकों की याद में भूटान का डाक टिकट संयुक्त रूप से जारी किया।

रुपे कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा

दोनों प्रधानमंत्रियों ने भूटान में औपचारिक रूप से भारतीय रुपे कार्ड के

इस्तेमाल की सुविधा शुरू की, जिससे भूटान आने वाले भारतीय यात्रियों को बहुत फायदा होगा और उन्हें नकदी लाने की जरूरत में कमी आएगी। इसके अलावा इस सुविधा से भूटान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं और मजबूत होंगी।

दोनों पक्षों ने इस परियोजना के नये चरण पर तेजी से काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसके तहत भूटान के बैंकों द्वारा रुपे कार्ड जारी करना शामिल है। रुपे कार्ड जारी होने के साथ भूटान में भारत के 'भीम' ऐप के इस्तेमाल का अध्ययन करने पर भी सहमति हुई, ताकि दोनों देशों के बीच नकद विहीन भुगतान को प्रोत्साहन मिल सके।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने थिम्पू में दक्षिण-एशियाई उपग्रह के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के समर्थन से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री डॉ. शेरिंग ने 2017 में दक्षिण एशिया उपग्रह (एसएएस) को लॉन्च करने के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की।

यह उपग्रह दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों के लिए उपहार है, जिसने भूटान को कम खर्च पर भूटान प्रसारण सेवा को सुगम बनाने में सहायता की है। इसके अलावा इस सुविधा से भूटान राज्य की परिसीमाओं के अंदर आपदा प्रबंधन क्षमताओं में भी इजाफा हुआ है।

भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के मद्देनजर एसएएस के सकारात्मक प्रभाव के सिलसिले में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान की आवश्यकताओं के अनुरूप एक अतिरिक्त ट्रांसपोंडर पर बढ़ी हुई बैंडविथ उपहार स्वरूप भूटानवासियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया।

दोनों राजनेताओं ने भूटान के लिए एक छोटा उपग्रह संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए आपस में गठबंधन करने पर भी सहमति जताई।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और भूटान के शोध एवं शिक्षा नेटवर्क के बीच इंटर-कनेक्शन या पारस्परिक संबंध का भी उद्घाटन किया। दोनों पक्षों ने यह बात रेखांकित की कि इस जुड़ाव से एक सूचना हाईवे सृजित होगा जिससे दोनों देशों के विश्वविद्यालयों एवं विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संवाद को काफी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान हुए ज्ञापनों/समझौतों की सूची

क्र.सं.	समझौता ज्ञापन/समझौते का नाम
1	भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत गणराज्य की सरकार और भूटान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के मध्य दक्षिण एशिया उपग्रह के उपयोग के लिए सैटकॉम नेटवर्क की स्थापना के बारे में समझौता ज्ञापन।
2	सूचना और संचार मंत्रालय, भूटान सरकार और वायु दुर्घटना जांच इकाई (एएआईयू) सूचना और संचार मंत्रालय भूटान सरकार तथा विमान दुर्घटना, जांच ब्यूरो नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य वायुयान दुर्घटना और हादसा जांच के संबंध में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।
3	भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन), राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी और भूटान के दूरसंचार विभाग और (ड्रंक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क ऑन पीरिंग एरेमांट) के बीच समझौता ज्ञापन।
4	पीटीसी इंडिया लिमिटेड और ड्रंकग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच मंगदेछु विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए विद्युत क्रम अनुबंध।
5	भूटान राष्ट्रीय कानून संस्थान और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के बीच न्यायिक शिक्षा और परस्पर आदान-प्रदान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
6	जिग्मे सिंगे वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ, थिम्पू, भूटान, और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, भारत के बीच दोनों पक्षों में कानूनी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन।
7	रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के बीच समझौता ज्ञापन।
8	रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के बीच समझौता ज्ञापन।
9	रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर के बीच समझौता ज्ञापन।
10	रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भूटान के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों के जन-केन्द्रित स्वरूप के साथ-साथ दोनों देशों के बीच गहन आध्यात्मिक तथा बौद्ध धर्म संबंधी जुड़ाव पर प्रकाश डाला।

उन्होंने भारत-भूटान संबंधों को नए मुकाम पर ले जाने के लिए दोनों देशों के युवाओं द्वारा शिक्षा और उच्च-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में साझेदारी करने के महत्व पर विशेष बल दिया।

भूटान सरकार के अनुरोध पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भूटान को उपलब्ध कराई जाने वाली सस्ती एलपीजी की मात्रा मौजूदा 700 एमटी से बढ़ाकर 1,000 एमटी प्रतिमाह किये जाने की घोषणा की, ताकि भूटान सरकार बढ़ती घरेलू जरूरतों को पूरा कर सके तथा उसे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पैठ बढ़ाने में सहायता मिल सके।

दोनों पक्षों ने भारत और भूटान के बीच युवाओं के आदान-प्रदान पर व्यापक बल देते हुए सहयोग के परंपरागत क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत बनाने तथा साथ ही साथ नए उभरते क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता प्रकट की। ■

ट्रिपल तलाक समाप्त करना आसान नहीं था: अमित शाह

नरेन्द्र मोदी का नाम भी समाज सुधारकों की श्रेणी में शामिल होगा

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 18 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशनल क्लब के मावलंकर सभागार में बोलते हुए कहा कि ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का रास्ता आसान नहीं था किंतु मोदी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण सफलता प्राप्त हुई। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान ने किया था।

श्री शाह ने कहा कि वोट बैंक बचाने के लिए तुष्टीकरण किया जाता है इससे देश के विकास की गति को नुकसान होता है, तुष्टीकरण सामाजिक समरसता के आड़े भी आती है किंतु पूर्व की सरकार केवल वोट बैंक के लालच के कारण इस कुप्रथा को समाप्त करने का विरोध करती रही। श्री शाह ने यह भी कहा कि गरीब और पिछड़ा किसी भी धर्म का हो उसे ऊपर उठाना चाहिए।

श्री शाह का कहना था कि इस कानून का जिन राजनीतिक दलों ने विरोध किया वह भी अपने मन के अंदर चाहते होंगे कि ट्रिपल तलाक खत्म हो। ट्रिपल तलाक कानून देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों के लिए है और यह कानून मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है क्योंकि ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना मुस्लिम बहनों और माताओं को सहनी पड़ती थी। उनका कहना था कि नारी को समानता का अधिकार प्राप्त हो इसलिए यह ट्रिपल तलाक समाप्त किया गया।

श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मोरक्को, टर्की, इंडोनेशिया सहित कई इस्लामिक और गैर-इस्लामिक देशों में भी 56 साल पहले ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर दिया था। किंतु हमें 56 साल इस काम को करने में लगे। श्री शाह ने आरिफ मोहम्मद खान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में ट्रिपल तलाक का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था।

श्री अमित शाह का कहना था कि साठ के दशक के बाद की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमारे देश के राष्ट्र-जीवन, सामाजिक जीवन को बड़ा नकारात्मक असर पहुंचा जिससे देश के गरीबों के विकास का कार्य रुक गया, किंतु 2014 में इस देश की जनता ने माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर इस तुष्टिकरण को तिलांजलि दे दी।

उन्होंने श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मोदीजी द्वारा सर्व-समावेशी विकास किया गया और यही कारण है कि देश की जनता ने मोदीजी को दोबारा सत्ता दी। श्री शाह ने आगे कहा कि मोदीजी की सरकार ने 5 साल में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया है।

उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल पेश करते समय को याद करते हुए कहा कि उन्होंने संसद में बिल का विरोध करने वाले सभी सांसदों को बैठकर सुना और सभी की दलीलें केवल वोटबैंक की राजनीति से प्रेरित थीं। विरोध करने वालों को न तो मुस्लिम बहनों की चिंता है न ही उनके बच्चों की चिंता है, उनको केवल वोट बैंक की चिंता है।

सांसद ओवैसी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहले भी बहुत सारे समाज सुधार के कार्यक्रमों में क्रिमिनल सजा तय की जा चुकी है। सती प्रथा, बाल विवाह आदि कई कुप्रथाएं समाप्त की गईं पर किसी ने विरोध नहीं किया, इन्हें खत्म करना भी चाहिए था,

क्योंकि यदि समय के साथ समाज नहीं बदलता है तो गंदे तालाब जैसा बन जाता है और समय के साथ बदलने वाला समाज निर्मल गंगा की तरह पवित्र हो जाता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक को गैर-इस्लामिक और गैर-संवैधानिक घोषित किया था, जज कोरियन साहब ने भी कहा था कि यदि यह व्यवस्था कुरान के अंदर पाप है तो कानून के अंदर कैसे मान्य हो सकती है।

श्री शाह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि ट्रिपल तलाक खत्म करने वाली प्रक्रिया के समर्थन में मेरा भी एक वोट शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि जब भी देश के समाज सुधारकों का नाम लिया जाएगा श्री नरेन्द्र मोदी का नाम भी समाज सुधारकों की श्रेणी में शामिल होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान के निदेशक डॉ. अनिर्बाण गांगुली भी उपस्थित थे। ■

अनुच्छेद 370 के रद्द होने से जम्मू कश्मीर, लद्दाख के निवासी बहुत लाभान्वित होंगे: रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 14 अगस्त को विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले से 'वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे।'

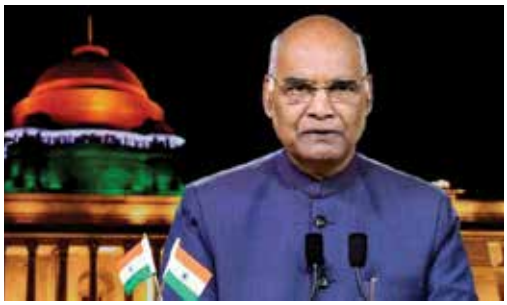

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्री कोविंद ने कहा, ''...मुझे विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती हैं।"

श्री कोविंद ने कहा, ''वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील क़ानूनों और प्रावधानों का उपयोग कर सकेंगे। 'शिक्षा का अधिकार' (आरटीई) कानून लागू होने से सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। 'सूचना का अधिकार' मिल जाने से, अब वहां के लोग जनहित से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; पारंपरिक रूप से वंचित रहे वर्गों के लोगों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी।"

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने और राज्य को विभाजित करने का फैसला लिया था। इससे जुड़े संकल्प एवं विधेयक को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू कश्मीर और लद्दाख- 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगे। ■

करदाताओं के विवादों के निपटारे के लिए 'सबका विश्वास' योजना 1 सितंबर से शुरू होगी

केंद्रीय बजट 2019-20 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने करदाताओं के लम्बित विवादों के निपटारे के लिए समाधान योजना-सबका विश्वास-2019 की घोषणा की थी। इस योजना को अब अधिसूचित कर दिया गया है और यह 1 सितंबर 2019 से शुरू होगी। योजना 31 दिसंबर, 2019 तक जारी रहेगी। सरकार को विश्वास है कि बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबधित अपने बकाया मामलों के समाधान के लिए इस योजना का लाभ उठाएंगे। ये सभी मामले अब जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इससे करदाता जीएसटी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

योजना के दो प्रमुख भाग विवाद समाधान और आम माफी है। विवाद समाधान का लक्ष्य अब जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलों का समाधान करना है। आम माफी के तहत करदाता को बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और करदाता कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रहेगा।

योजना का सबसे आकर्षक प्रस्ताव सभी प्रकार के मामलों में बकाया कर से बड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज,जुर्माना और अर्थ दंड में पूर्ण राहत देना है। इन सभी मामलों में किसी भी प्रकार का अन्य ब्याज,जुर्माना और अर्थ दंड नहीं लगाया जाएगा और इसके साथ ही अभियोजन से भी पूरी छूट मिलेगी।

योजना के अंतर्गत न्यायिक या अपील में लंबित सभी मामलों में 50 लाख या इससे कम की चुंगी के मामले में 70 प्रतिशत की राहत और 50 लाख से अधिक के मामलों में 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी। यह छूट जांच और लेखा परीक्षण के अंतर्गत चल रहे ऐसे मामलों में जहां और चुंगी परिमाणित कर ली गई हो और संबधित पक्ष को सूचित कर दी गई हो, या विवरण में 30 जून, 2019 या उससे पहले स्वीकार कर लिया गया हो, में मिलेगी।

स्थायी चुंगी मांग के मामले में जहां अपील लंबित न हो उन मामलों में 50 लाख या उससे कम की स्थिति में 60 प्रतिशत की राहत और 50 लाख से अधिक की स्थिति में 40 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। स्वैच्छिक घोषणा की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को केवल स्वैच्छिक चुंगी की पूर्ण राशि देनी होगी।

योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में करदाताओं को लंबित करों से राहत दिलाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में छोटे करदाताओं के लंबित मामलों का समाधान करना है। केंद्र सरकार ने सभी संबधित लोगों से सबका विश्वास योजना का लाभ उठाने और नई शुरुआत करने का आह्वान किया है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भूटान में पारो पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक

भूटान आगमन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भूटानवासी

नई दिल्ली में रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कलाई पर राखी बांधती महिलाएं व बच्चियां

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19